



Neutral Citation No. - 2026: AHC:14963-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 413 के तहत आपराधिक अपील दोषपूर्ण संख्या - 6/2026

रतन खन्ना

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : महेंद्र प्रताप सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत

वर्तमान आपराधिक मामला अपराध संख्या 558/2016 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 41/2017 (राज्य बनाम विवेक त्रिपाठी और अन्य) के तहत धारा 307, 120-बी, 147, 148, 149 आईपीसी, पुलिस स्टेशन चकरी, जिला कानपुर नगर के तहत अपील में अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 17, कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 16.05.2023 और 17.05.2023 के खिलाफ बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 41 के तहत दायर की गई है। जिसमें प्रतिपक्षी संख्या 2, 3 और 4 को भा.द.सं. की धारा 307, 120-बी, 147, 148, 149 के तहत अपराधों के लिए बरी कर दिया गया है और प्रतिपक्षी संख्या 5 को धारा 120-बी के तहत अपराधों के लिए बरी कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध के लिए सजा सुनाई गई है और आजीवन कारावास के स्थान पर 8 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।

अपील समय से 878 दिनों (लगभग ढाई वर्ष) से अधिक है। हमें विलंब माफी आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र में बताए गए स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं लगता है। देरी के कारण शपथपत्र के पैराग्राफ सं. 4, 5 और 6 में बताए गए हैं जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा



"4. यह कि इस माननीय न्यायालय में जाने में अपीलकर्ता की ओर से कोई जानबूझकर या इरादापूर्वक देरी नहीं की गई है और कारण अपीलकर्ता के नियंत्रण से बाहर हैं जैसा कि इसके बाद उल्लेख किया गया है।

5. अपीलकर्ता को आर्थिक कठिनाइयों और वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के कारण इस माननीय न्यायालय में आने में अनजाने में देरी हुई है।

6 यह कि अपीलकर्ता की आयु 96 वर्ष से अधिक है और वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है। अपीलकर्ता वित्तीय कठिनाइयों से भी पीड़ित है और इसलिए वह अधिवक्ता की व्यवस्था करने में भी असमर्थ था जो समय के भीतर आक्षेपित आदेश को चुनौती देने के लिए अपनी आपराधिक अपील तैयार कर सके।

स्पष्ट है, अपील दायर करने में दिन-प्रतिदिन की देरी के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। यह नहीं बताया गया है कि अपीलकर्ता को हुई वित्तीय कठिनाइयों को कैसे और कब दूर किया गया। अपीलकर्ता का बेटा इस घटना में घायल हो गया था जो सत्र परीक्षण का विषय था। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि अपीलकर्ता का बेटा अपीलकर्ता की ओर से मामले की पैरवी क्यों नहीं कर सका और अपीलकर्ता के नाम पर अपील दायर क्यों की।

विलम्ब माफी आवेदन और परिणामस्वरूप अपील **खारिज** कर दी जाती है।

जनवरी 21, 2026

विपाशा

(न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा